अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका
ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

विकसित भारत 2047 : युवाओं की भूमिका और भविष्य की दिशा

डॉ. नरेन्द्र कुमार
सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर

डॉ. भावना
सहायक आचार्य, इतिहास विभाग,
राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़

सारांश

"विकसित भारत 2047 : युवाओं की भूमिका और भविष्य की दिशा" विषय भारतीय विकास यात्रा के उस महत्वपूर्ण चरण का विश्लेषण करता है जिसमें युवाओं को राष्ट्र निर्माण का केंद्रीय स्तंभ माना गया है। वर्ष 2047 जो भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने का प्रतीक है, को ध्यान में रखते हुए यह शोधपत्र इस बात की पड़ताल करता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है तथा उनके समक्ष कौन–कौन सी चुनौतियाँ और अवसर मौजूद हैं। भारत विश्व का सबसे युवा देश है जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग युवाओं का है। यह जनसांख्यिकीय लाभ (Demographic Dividend) तभी सार्थक हो सकता है जब युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर तथा नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए। इस शोधपत्र में शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यावरणीय जागरूकता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे विभिन्न आयामों के माध्यम से युवाओं की भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन भारत सरकार की प्रमुख नीतियों जैसे Skill India, Digital India, Startup India आदि के संदर्भ में युवाओं की सहभागिता का मूल्यांकन करता है। शोधपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भविष्य की दिशा में युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी सृजक (Job Creators), नवप्रवर्तक (Innovators) और जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करना आवश्यक है।

अंततः, यह शोधपत्र निष्कर्ष निकालता है कि यदि युवाओं की ऊर्जा, कौशल और रचनात्मकता को सही दिशा में मार्गदर्शित किया जाए, तो "विकसित भारत 2047" का लक्ष्य न केवल संभव है बल्कि भारत वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकता है।

मुख्य शब्दःविकसित भारत 2047, युवा शक्ति, जनसांख्यिकीय लाभ, कौशल विकास, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नवाचार, रोजगार, उद्यमिता, सामाजिक उत्तरदायित्व

प्रस्तावना

"विकसित भारत 2047" भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष (2047) तक देश को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर, समावेशी और वैश्विक स्तर पर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की एक व्यापक राष्ट्रीय परिकल्पना है। यह केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय, तकनीकी प्रगति, पर्यावरणीय संतुलन, सुशासन और मानव विकास जैसे बहुआयामी आयामों को समाहित करता है। इस संदर्भ में भारत की युवा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उभरकर सामने आती है जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

भारत आज विश्व के उन देशों में अग्रणी है जहाँ युवा जनसंख्या का अनुपात अत्यधिक है। यह स्थिति भारत को "जनसांख्यिकीय लाभ" (Demographic Dividend) प्रदान करती है जो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है किंतु यह अवसर तभी वास्तविक लाभ में परिवर्तित हो सकता है जब युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाएँ, रोजगार के अवसर तथा नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए। यदि इन आवश्यकताओं की पूर्ति

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

नहीं होती तो यही जनसंख्या बोझ भी बन सकती है। अतः यह आवश्यक है कि युवाओं की ऊर्जा और क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग किया जाए।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और वैश्वीकरण ने विकास के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया है। ऐसे में युवाओं के सामने नए अवसरों के साथ–साथ नई चुनौतियाँ भी उपस्थित हुई हैं। एक ओर जहाँ स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नवाचार के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिल रहे हैं वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी, कौशल–असंतुलन, मानसिक तनाव और प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याएँ भी बढ़ रही हैं।

इस शोधपत्र का उद्देश्य "विकसित भारत 2047" के संदर्भ में युवाओं की भूमिका का समग्र विश्लेषण करना है। इसमें यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि युवा किस प्रकार राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं और उन्हें किस प्रकार की नीतिगत एवं सामाजिक सहायता की आवश्यकता है। साथ ही, यह अध्ययन युवाओं के समक्ष उपस्थित चुनौतियों की पहचान कर उनके समाधान की दिशा में सुझाव प्रस्तुत करेगा।

अतः स्पष्ट है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब युवा न केवल अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए राष्ट्रहित में सक्रिय भूमिका निभाएँ। युवा शक्ति की ऊर्जा, नवाचार क्षमता और सकारात्मक दृष्टिकोण ही भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का आधार बनेगी।

विकसित भारत 2047 : अवधारणा एवं लक्ष्य

"विकसित भारत 2047" की अवधारणा भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक देश को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की है जो आर्थिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीकी रूप से उन्नत तथा वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली हो। यह अवधारणा केवल आय और उत्पादन में वृद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन की गुणवत्ता, समान अवसर, सुशासन, पर्यावरणीय संतुलन और मानवीय मूल्यों के समग्र विकास को भी समाहित करती है। इस प्रकार "विकसित भारत" का अर्थ एक ऐसे राष्ट्र से है जहाँ विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से पहुँचे और सतत विकास (Sustainable Development) के सिद्धांतों का पालन किया जाए।

अवधारणा के स्तर पर विकसित राष्ट्र की पहचान कुछ प्रमुख संकेतकों से की जाती है जैसे–उच्च प्रति व्यक्ति आय, उन्नत औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, उच्च मानव विकास सूचकांक (HDI), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ तथा तकनीकी नवाचार में अग्रणी भूमिका। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण जैसे तत्व भी विकसित राष्ट्र की परिभाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

"विकसित भारत 2047" के प्रमुख लक्ष्यों को विभिन्न आयामों में समझा जा सकता है। आर्थिक दृष्टि से लक्ष्य है कि भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जहाँ उत्पादन, निर्यात, निवेश और रोजगार के अवसरों में निरंतर वृद्धि हो। इसके लिए विनिर्माण (Manufacturing), सेवा क्षेत्र, कृषि आधुनिकीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है। सामाजिक दृष्टि से लक्ष्य एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना है जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएँ सभी नागरिकों को उपलब्ध हों। इसके साथ ही, सामाजिक असमानताओं को कम करना, महिलाओं और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना भी इस लक्ष्य का महत्वपूर्ण भाग है।

तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से "विकसित भारत 2047" का उद्देश्य नवाचार, अनुसंधान एवं विकास (R&D), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अंतरिक्ष विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करना है। इसके लिए शिक्षा प्रणाली को कौशल आधारित और अनुसंधान उन्मुख बनाना आवश्यक है ताकि युवा नई तकनीकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। पर्यावरणीय दृष्टि से लक्ष्य सतत विकास को सुनिश्चित करना है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण,

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीतियाँ शामिल हैं। "ग्रीन इंडिया" और "क्लाइमेट एक्शन" जैसी पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, भारत का लक्ष्य केवल एक विकसित राष्ट्र बनना ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक जिम्मेदार और प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरना भी है। इसके लिए कूटनीति, व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना आवश्यक है। अतः "विकसित भारत 2047" एक बहुआयामी और दूरदर्शी लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए सरकार, समाज और विशेष रूप से युवाओं की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। यह लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब विकास के सभी आयामों में संतुलन स्थापित करते हुए समग्र और सतत प्रगति सुनिश्चित की जाए।

भारत में युवाओं की वर्तमान स्थिति

भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है जहाँ लगभग 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात अत्यधिक है। यह युवा शक्ति भारत के लिए एक महत्वपूर्ण "जनसांख्यिकीय लाभ" (Demographic Dividend) का प्रतिनिधित्व करती है जो आर्थिक विकास, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक सशक्त आधार प्रदान करती है किंतु इस संभावित लाभ का वास्तविक उपयोग तभी संभव है जब युवाओं की वर्तमान स्थिति को समग्र रूप से समझकर उनके विकास के लिए उपयुक्त नीतियाँ और अवसर सुनिश्चित किए जाएँ।

शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि, डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म का विस्तार तथा नई शिक्षा नीति (NEP) जैसे सुधारात्मक कदमों ने युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं। इसके बावजूद शिक्षा की गुणवत्ता, व्यावसायिक कौशल (Vocational Skills) की कमी और पाठ्यक्रम एवं उद्योग की आवश्यकताओं के बीच असंगति जैसी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं। कई युवा डिग्री तो प्राप्त कर लेते हैं किंतु उनके पास रोजगारोन्मुख कौशलों का अभाव होता है जिससे रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

रोजगार की दृष्टि से युवाओं की स्थिति एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आती है। भारत में बेरोजगारी दर, विशेष रूप से शिक्षित युवाओं के बीच, चिंता का विषय बनी हुई है। एक ओर जहाँ सरकारी और निजी क्षेत्रों में सीमित अवसर हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप, कई युवा अस्थायी या कम वेतन वाले कार्यों में संलग्न होने के लिए विवश होते हैं। हालांकि, स्टार्टअप संस्कृति, फ्रीलांसिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने स्वरोजगार के नए अवसर भी प्रदान किए हैं जिससे कुछ हद तक इस समस्या का समाधान संभव हुआ है।

तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में भारतीय युवा तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुँच ने युवाओं को वैश्विक ज्ञान और अवसरों से जोड़ दिया है। डिजिटल साक्षरता में वृद्धि, ऑनलाइन शिक्षा, ई–कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें नई दिशा प्रदान की है। फिर भी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच "डिजिटल विभाजन" (Digital Divide) एक प्रमुख समस्या है जो सभी युवाओं को समान अवसर प्राप्त करने से रोकता है।

सामाजिक और मानसिक दृष्टि से भी युवाओं की स्थिति बहुआयामी है। एक ओर युवा सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जागरूक और सक्रिय हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा का दबाव, बेरोजगारी और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी बढ़ रही हैं। यह स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि युवाओं के समग्र विकास के लिए केवल आर्थिक और शैक्षिक अवसर ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी आवश्यक है।

ग्रामीण और शहरी युवाओं की स्थिति में भी स्पष्ट अंतर देखा जाता है। जहाँ शहरी क्षेत्रों के युवाओं को शिक्षा, तकनीक और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, शिक्षा की सीमित गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों का अभाव युवाओं के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। यह असमानता समावेशी विकास के मार्ग में एक बड़ी चुनौती है।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

अतः स्पष्ट है कि भारत के युवाओं की वर्तमान स्थिति संभावनाओं और चुनौतियों का मिश्रण है। यदि इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जाए और युवाओं को उचित दिशा, संसाधन और अवसर प्रदान किए जाएँ तो यही युवा शक्ति "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य को साकार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका

राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया केवल शासन या नीतियों तक सीमित नहीं होती बल्कि यह समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय सहभागिता से संचालित होती है। इस संदर्भ में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ऊर्जा, नवाचार, साहस और परिवर्तनशील दृष्टिकोण के प्रतीक होते हैं। "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य की प्राप्ति में युवा न केवल वर्तमान के सहभागी हैं बल्कि भविष्य के निर्माता भी हैं। उनकी सोच, कार्यशैली और दृष्टिकोण ही राष्ट्र की दिशा और गति को निर्धारित करते हैं।

आर्थिक विकास के क्षेत्र में युवा शक्ति एक प्रमुख प्रेरक तत्व है। उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि और डिजिटल अर्थव्यवस्था में युवाओं की भागीदारी उत्पादन, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है। विशेष रूप से स्टार्टअप संस्कृति और उद्यमिता के माध्यम से युवा नए व्यवसाय स्थापित कर न केवल स्वयं के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

नवाचार और तकनीकी प्रगति में भी युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान युग डिजिटल और तकनीकी क्रांति का युग है जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा विज्ञान, रोबोटिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। भारतीय युवा इन क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहे हैं। नई तकनीकों के विकास और उनके उपयोग के माध्यम से युवा न केवल आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं बल्कि समाज की समस्याओं के समाधान भी खोज रहे हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी युवाओं की भूमिका उल्लेखनीय है। युवा समाज में जागरूकता फैलाने, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने और समानता, न्याय तथा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रहते हैं। वे शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर जनजागरूकता अभियान चलाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार, युवा एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र को सशक्त बनाने में सहायक होती है। युवा मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग कर बेहतर नेतृत्व के चयन में योगदान देते हैं। इसके अलावा, वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर, नीतियों पर विचार–विमर्श कर और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से शासन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन जैसी समस्याएँ आज वैश्विक चुनौती बन चुकी हैं। युवा इन मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने, सतत विकास के सिद्धांतों को अपनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए नवाचारपूर्ण उपायों को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका बहुआयामी और निर्णायक है। वे केवल विकास की प्रक्रिया के सहभागी नहीं बल्कि उसके प्रेरक और मार्गदर्शक भी हैं। यदि युवाओं को सही दिशा, अवसर और प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, तो उनकी ऊर्जा और रचनात्मकता भारत को 2047 तक एक विकसित, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

युवाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

भारत के युवा आज एक ऐसे संक्रमणकालीन दौर से गुजर रहे हैं जहाँ एक ओर उनके सामने असीमित अवसर उपलब्ध हैं वहीं दूसरी ओर अनेक जटिल चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य को साकार करने के लिए इन चुनौतियों की पहचान और उनका प्रभावी समाधान अत्यंत आवश्यक है। सबसे प्रमुख चुनौती बेरोजगारी और अधरोजगारी (Underemployment) की है। भारत में

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

बड़ी संख्या में युवा शिक्षित होने के बावजूद उपयुक्त रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे एक प्रमुख कारण कौशल–असंतुलन (Skill Mismatch) है जहाँ शिक्षा प्रणाली और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य का अभाव है। परिणामस्वरूप, कई युवा अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते जिससे उनकी उत्पादकता और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित होते हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता भी एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आती है। यद्यपि शिक्षा के प्रसार में वृद्धि हुई है फिर भी व्यावहारिक ज्ञान, अनुसंधान क्षमता और नवाचार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में रटने (rote learning) की प्रवृत्ति अधिक है जिससे युवाओं में आलोचनात्मक सोच (critical thinking) और समस्या समाधान की क्षमता का पूर्ण विकास नहीं हो पाता। डिजिटल युग में "डिजिटल विभाजन" (Digital Divide) भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। जहाँ शहरी क्षेत्रों के युवा उन्नत तकनीकी संसाधनों और इंटरनेट सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं वहीं ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के युवा इन सुविधाओं से वंचित हैं। यह असमानता शिक्षा, रोजगार और सूचना तक पहुँच के अवसरों को प्रभावित करती है जिससे समावेशी विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

मानसिक स्वास्थ्य की समस्या भी आज के युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रही है। प्रतिस्पर्धा का दबाव, बेरोजगारी की चिंता, पारिवारिक अपेक्षाएँ और सामाजिक तुलना (social comparison) के कारण युवा तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों को प्रभावित करती है।

सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। लैंगिक असमानता, सामाजिक भेदभाव और अवसरों की असमान उपलब्धता युवाओं के समग्र विकास में बाधक हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित वर्गों के युवाओं को इन समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त तेजी से बदलती तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण युवाओं पर निरंतर स्वयं को अद्यतन (upskill) करने का दबाव भी बना रहता है। यदि युवा समय के साथ अपने कौशलों को विकसित नहीं करते तो वे रोजगार के अवसरों से पीछे छूट सकते हैं।

अतः स्पष्ट है कि युवाओं के समक्ष उपस्थित ये चुनौतियाँ बहुआयामी और जटिल हैं। इनका समाधान केवल नीतिगत हस्तक्षेप से ही नहीं बल्कि समाज, शिक्षा प्रणाली और स्वयं युवाओं के समन्वित प्रयासों से संभव है। यदि इन समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाए तो युवा अपनी पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं और "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सरकारी पहलें एवं नीतियाँ

"विकसित भारत 2047" के लक्ष्य की प्राप्ति में सरकार की नीतियाँ और योजनाएँ युवाओं के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएँ प्रारंभ की हैं जिनका उद्देश्य युवाओं को शिक्षित, कुशल, आत्मनिर्भर तथा नवाचारी बनाना है। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर मिलते हैं बल्कि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रेरित होते हैं।

सबसे प्रमुख पहल Skill India Mission (कौशल भारत मिशन) है जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगोन्मुख कौशल प्रदान करना है। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) तथा कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से युवाओं को व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे रोजगार के लिए तैयार हो सकें। दूसरी महत्वपूर्ण पहल Digital India (डिजिटल भारत अभियान) है जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार, ई–गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाता है। इससे युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर प्राप्त होते हैं।

उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए Startup India (स्टार्टअप भारत योजना) एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता, कर में छूट, सरल नियम तथा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

सृजन कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु National Education Policy 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, कौशल आधारित और लचीला बनाना है ताकि युवा आधुनिक तकनीकी और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार हो सकें।

इसके अतिरिक्त, Make in India (मेक इन इंडिया) और Atmanirbhar Bharat Abhiyan (आत्मनिर्भर भारत अभियान) जैसी योजनाएँ देश में औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती हैं जिससे युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। सामाजिक विकास के क्षेत्र में National Service Scheme (राष्ट्रीय सेवा योजना) तथा Nehru Yuva Kendra Sangathan (नेहरू युवा केंद्र संगठन) जैसी संस्थाएँ युवाओं को सामाजिक सेवा, नेतृत्व विकास और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती हैं।

अतः स्पष्ट है कि ये सभी सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और इनकी पहुँच प्रत्येक युवा तक हो, तो यह "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य को प्राप्त करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगी।

भविष्य की दिशा एवं संभावनाएँ

"विकसित भारत 2047" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान नीतियों और प्रयासों के साथ–साथ भविष्य की स्पष्ट दिशा भी निर्धारित की जाए। यह दिशा केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित न होकर सामाजिक, तकनीकी, शैक्षिक और पर्यावरणीय संतुलन को भी समाहित करे। इस परिप्रेक्ष्य में युवाओं की भूमिका अत्यंत निर्णायक बन जाती है क्योंकि वही भविष्य के भारत के निर्माणकर्ता हैं।

भविष्य की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौशल आधारित शिक्षा (Skill-based Education) का विस्तार है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को व्यावहारिक, रोजगारोन्मुख और नवाचार केंद्रित बनाना आवश्यक है। नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, रोबोटिक्स और डिजिटल मार्केटिंग को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि युवा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार हो सकें।

तकनीकी नवाचार और डिजिटल परिवर्तन भी भविष्य की प्रमुख दिशा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार, स्टार्टअप संस्कृति के विकास और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश के माध्यम से भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाया जा सकता है। युवा इन क्षेत्रों में नई खोजों, तकनीकी समाधान और उद्यमिता के माध्यम से देश की प्रगति को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्थानीय संसाधनों का उपयोग, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा और छोटे एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) का विकास युवाओं के माध्यम से संभव है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि देश की आर्थिक स्वतंत्रता भी सुदृढ़ होगी। पर्यावरणीय दृष्टि से भविष्य की दिशा सतत विकास (Sustainable Development) की ओर केंद्रित होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे मुद्दों पर युवाओं को जागरूक और सक्रिय बनाना आवश्यक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नवाचार भविष्य के भारत को सुरक्षित और संतुलित बना सकते हैं।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी भारत के युवाओं के लिए अनेक संभावनाएँ हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, शिक्षा, तकनीकी सहयोग और कूटनीतिक संबंधों में युवाओं की भागीदारी भारत को वैश्विक मंच पर सशक्त बना सकती है। डिजिटल कनेक्टिविटी और वैश्वीकरण के इस युग में भारतीय युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन विश्व स्तर पर कर सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से भविष्य की दिशा एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की ओर होनी चाहिए। इसमें लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, और समान अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। युवा इन मूल्यों को अपनाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।अतः स्पष्ट है कि भविष्य की दिशा और संभावनाएँ अत्यंत व्यापक हैं जिनमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। यदि सही नीतियों, शिक्षा, तकनीकी नवाचार और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया जाए तो वे न केवल अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं बल्कि "विकसित भारत 2047" के सपने को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

समाधान एवं सुझाव

"विकसित भारत 2047" के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि युवाओं के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का प्रभावी समाधान खोजा जाए और उनके समग्र विकास हेतु व्यावहारिक एवं दूरदर्शी सुझाव प्रस्तुत किए जाएँ। समाधान केवल नीतिगत स्तर तक सीमित न होकर शिक्षा, समाज, उद्योग तथा स्वयं युवाओं के संयुक्त प्रयासों पर आधारित होना चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण समाधान शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार है। वर्तमान शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, कौशल आधारित और रोजगारोन्मुख बनाना आवश्यक है। विद्यालय और उच्च शिक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए। इंटर्नशिप, प्रशिक्षण (Training) और व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर युवाओं को वास्तविक कार्य अनुभव प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ ही अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि युवा केवल ज्ञान के उपभोक्ता नहीं, बल्कि सृजनकर्ता बन सकें।

दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव रोजगार सृजन और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर नए उद्योगों, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देना चाहिए। युवाओं को आसान ऋण, तकनीकी सहायता और बाजार तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए जिससे वे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें। इससे बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है और आर्थिक विकास को गति मिलती है।

तीसरा महत्वपूर्ण पहलू डिजिटल और तकनीकी सशक्तिकरण है। सभी युवाओं को समान रूप से डिजिटल संसाधनों और इंटरनेट सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि "डिजिटल विभाजन" को समाप्त किया जा सके। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नई तकनीकों का उपयोग सिखाया जाए जिससे वे डिजिटल अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी कर सकें।

चौथा, मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवाओं का सुदृढ़ीकरण अत्यंत आवश्यक है। शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों पर काउंसलिंग सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे युवा तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट सकें। इसके साथ ही परिवार और समाज को भी युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाना आवश्यक है। पाँचवाँ, सामाजिक समावेशन और समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अवसरों की असमानता को कम किया जाना चाहिए। महिलाओं, वंचित वर्गों और विशेष आवश्यकता वाले युवाओं को शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता में समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। छठा, युवाओं की नीति निर्माण में भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। युवाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल कर उनकी सोच और नवाचार को नीतियों में स्थान दिया जाना चाहिए। इससे नीतियाँ अधिक प्रभावी और यथार्थपरक बनेंगी।

अंततः, नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास भी अत्यंत आवश्यक है। युवाओं को केवल आर्थिक सफलता तक सीमित न रखते हुए, उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करना चाहिए जो समाज, राष्ट्र और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उनका पालन करे। इस प्रकार, यदि इन सुझावों को समन्वित और प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो युवाओं की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग संभव होगा और वे "विकसित भारत 2047" के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे।

निष्कर्ष

"विकसित भारत 2047" का लक्ष्य केवल एक राष्ट्रीय संकल्प नहीं बल्कि भारत के समग्र और सतत विकास की दिशा में एक दूरदर्शी दृष्टि है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका अत्यंत केंद्रीय और निर्णायक है क्योंकि वे न केवल वर्तमान के सक्रिय सहभागी हैं बल्कि भविष्य के निर्माणकर्ता भी हैं। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भारत की युवा शक्ति में अपार संभावनाएँ निहित हैं जो देश को आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती हैं।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 14-Issue 04, (Oct-Dec 2026)

हालाँकि, यह भी स्पष्ट है कि युवाओं के समक्ष अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं जैसे बेरोजगारी, कौशल–असंतुलन, शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल विभाजन तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ। इन चुनौतियों का समाधान किए बिना "विकसित भारत" की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार करना संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, समाज, शैक्षणिक संस्थान और स्वयं युवा मिलकर इन समस्याओं के समाधान के लिए समन्वित प्रयास करें।

सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ–जैसे कौशल विकास, डिजिटल सशक्तिकरण, उद्यमिता प्रोत्साहन और शिक्षा सुधार युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और उनकी पहुँच प्रत्येक युवा तक हो तो यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकती हैं। साथ ही, युवाओं को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए निरंतर आत्मविकास, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करना होगा।

अंततः यह कहा जा सकता है कि "विकसित भारत 2047" का सपना तभी साकार होगा जब युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और रचनात्मकता को सही दिशा में मार्गदर्शित किया जाए। एक शिक्षित, कुशल, जागरूक और जिम्मेदार युवा ही भारत को एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकता है। अतः युवा शक्ति ही विकसित भारत की आधारशिला है और वही इस स्वप्न को वास्तविकता में परिवर्तित करने की सबसे बड़ी आशा भी है।

संदर्भ

1. अग्रवाल, आर. सी. भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास. नई दिल्ली : एस. चंद एंड कंपनी, 2018।
2. सिंह, योगेन्द्र. भारतीय समाजरू संरचना और परिवर्तन. नई दिल्ली : रावत प्रकाशन, 2016।
3. तिवारी, वी. के. आधुनिक भारत का आर्थिक विकास. वाराणसी : विश्वभारती प्रकाशन, 2019।
4. योजना आयोग. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017). नई दिल्ली : भारत सरकार, 2013।
5. नीति आयोग. भारत@75 : न्यू इंडिया विज़न दस्तावेज़. नई दिल्ली : भारत सरकार, 2018।
6. भारत सरकार. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय, 2020।
7. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय. कौशल भारत मिशन रिपोर्ट. नई दिल्ली : भारत सरकार, 2021।
8. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय. डिजिटल भारत कार्यक्रम : एक अवलोकन. नई दिल्ली : भारत सरकार, 2022।
9. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग. स्टार्टअप इंडिया पहल रिपोर्ट. नई दिल्ली : भारत सरकार, 2021।
10. विश्व बैंक. विश्व विकास रिपोर्ट 2020. वाशिंगटन डी.सी. : विश्व बैंक, 2020।
11. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP). मानव विकास रिपोर्ट 2021. न्यूयॉर्क : यूएनडीपी, 2021।
12. शर्मा, आर. के. युवा और राष्ट्र निर्माण. जयपुर : राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2017।
13. वर्मा, एस. पी. भारत में युवाओं की समस्याएँ और समाधान. दिल्ली : विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2019।
14. प्रेस सूचना ब्यूरो. "विकसित भारत 2047 : सरकार की पहलें." नई दिल्ली : भारत सरकार, 2023।
15. हिंदुस्तान टाइम्स. "भारत में युवा शक्ति और विकास की संभावनाएँ." नई दिल्ली, 2022।